Date 11.05.26

Publication: Business Standard (H)

कोल इंडिया 1 लाख करोड़ रु. खर्च करेगी

पृष्ठ 1 का शेष...

कोल इंडिया अब पिटहेड स्टॉक को कम करने की योजना बना रही है। इस बदलाव का प्रमुख स्तंभ फर्स्ट-माइल कनेक्टिविटी (एफएमसी) यानी खदान से मुख्य परिवहन स्थल तक बुनियादी ढांचे का विस्तार है। इस योजना के तहत कोल इंडिया कोयला निकासी और हैंडलिंग दक्षता में सुधार के लिए अगले 4 साल में कन्वेयर सिस्टम, साइलो और मशीनीकृत रेल-लोडिंग सुविधाओं पर लगभग 25,000 करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना बना रही है। कंपनी वर्तमान में 43.2 करोड़ टन की हैंडलिंग क्षमता वाली 46 एफएमसी परियोजनाओं का संचालन कर रही है। इस साल 13.3 करोड़ टन क्षमता वाली 13 और परियोजनाएं जोड़ी जा रही हैं। वित्त वर्ष 2030 तक कोल इंडिया का लक्ष्य एफएमसी परियोजनाओं की संख्या को बढ़ाकर 94 करना है, जिससे कुल हैंडलिंग क्षमता लगभग 99.5 करोड़ टन तक बढ़ जाएगी। पूंजीगत खर्च को बढ़ावा देने से कोल इंडिया को कोयला गैसीकरण, थर्मल पावर और महत्त्वपूर्ण खनिजों में विविधीकरण रणनीति का समर्थन करने में भी मदद मिलेगी। कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड (बीएचईएल) की साझेदारी में ओडिशा के लखनपुर में 25,000 करोड़ रुपये की कोयला गैसीकरण परियोजना विकसित कर रही है।

कोल इंडिया और दामोदर वैली कॉर्पोरेशन (डीवीसी) संयुक्त रूप से चंद्रपुरा में 1,600 मेगावाट की अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना विकसित कर रही हैं, जिसमें लगभग 20,000 करोड़ रुपये का निवेश होने का अनुमान है। इस परियोजना के वित्त वर्ष 2031 तक चालू होने की उम्मीद है। साईराम ने कहा कि कोल इंडिया अपने इतिहास में पहली बार विविधीकरण परियोजनाओं के लिए पूंजी जुटाने की खातिर ऋण बाजार का रुख कर सकती है। उन्होंने कहा, 'कोल इंडिया पारंपरिक रूप से कर्ज मुक्त कंपनी रही है। ऐतिहासिक रूप से हमने ऋण बाजारों का रुख नहीं किया है।' उन्होंने कहा कि गैसीकरण परियोजना के लिए बैंकरों की पहचान पहले ही कर ली गई है। कंपनी चालू वित्त वर्ष के दौरान दो अतिरिक्त सहायक कंपनियों को सूचीबद्ध करने की भी योजना बना रही है। इन कंपनियों में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड और महानदी कोलफील्ड्स शामिल हैं।

वित्त वर्ष 2026 में कोल इंडिया का समेकित शुद्ध लाभ 11 फीसदी घटकर 31,071 करोड़ रुपये रहा जबकि परिचालन आय लगभग 1.68 लाख करोड़ रुपये पर सपाट रही। कोल इंडिया देश के कुल कोयला उत्पादन में 80 फीसदी से अधिक का योगदान करती है।

Date 11.05.26

Publication: Business Standard

"ANNUAL CAPEX MAY VARY BETWEEN ₹18,000 CRORE AND ₹25,000 CRORE. THIS RANGE IS BECAUSE DIVERSIFICATION PROJECTS ARE DYNAMIC AND MARKET DEVELOPMENTS"

B Sairam

Chairman-cum-Managing Director, Coal India

PAGE 4 Q&A

Major reforms, consolidation in the works: Coal India CMD

■ NTPC to soon seek AEC nod to set up its first nuclear plant 4 ▸

Date 11.05.26

Publication: Business Standard (H)

चालू वित्त वर्ष में कोल इंडिया लिमिटेड में बड़े सुधार व समेकन की तैयारी: सीएमडी

विश्व की सबसे बड़ी कोयला खनन कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) बड़े रणनीतिक परिवर्तनों में के लिए तैयार हो रही है। सरकारी कंपनी अपनी खदानों में पड़े कोयले के स्टॉक को कम करने, निकासी संबंधी बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने, विविधीकरण परियोजनाओं को आगे बढ़ाने और परिचालन सुधारों को तेज करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। नई दिल्ली में साकेत कुमार और सुधीर पाल सिंह के साथ बातचीत में सीआईएल के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) बी साईराम ने कंपनी की आपूर्ति-केंद्रित रणनीति, गैसीकरण प रियोजनाओं, धन जुटाने की योजनाओं, सहायक कंपनियों की ताजा लिस्टिंग और ताप बिजली के विस्तार के बारे में बात की। संपादित अंश:

आपकी सूची में शीर्ष 3 प्राथमिकताएं क्या हैं?

कोल इंडिया की 3 प्राथमिकताओं में आपूर्ति या कोयले का उठान, उत्पादन और बड़े पैमाने पर सुधार और समेकन शामिल है। आपूर्ति अब सर्वोच्च प्राथमिकता बन गई है क्योंकि हमने इस वर्ष अपनी खदानों में लगभग 13 करोड़ टन कोयले के स्टॉक के साथ शुरुआत की थी। हमारा लक्ष्य धीरे धीरे भंडारण घटाकर लगभग 5 करोड़ टन करना है, जिससे परिचालन संबंधी लचीलापन बना रहे। पिछले साल हमने 76.8 करोड़ टन उत्पादन किया, और इन्वेंट्री वार्षिक उत्पादन का लगभग 20 प्रतिशत थी। हमारा प्रयास धीरे धीरे इस अनुपात को 10 प्रतिशत के करीब लाना है।

क्या समेकन में सहायक कंपनियों की लिस्टिंग भी शामिल है?

हां, निश्चित रूप से। पिछले साल, हमने बीसीसीएल और सीएमपीडीआई को सूचीबद्ध किया, और दोनों ने अच्छा प्रदर्शन किया। खनन क्षेत्र की कंपनियों में निवेशकों के उत्साह से हमारा भरोसा मजबूत हुआ। सूचीबद्धता के बाद सीएमपीडीआई में लगभग 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि बीसीसीएल में लगभग 43 प्रतिशत की वृद्धि हुई। आज सीएमपीडीआई का बाजार पूंजीकरण (एम-कैप) लगभग 14,000 करोड़ रुपये है, जबकि बीसीसीएल का एम-कैप लगभग 15,500 करोड़ रुपये है। इस साल हम साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स और महानदी कोलफील्ड्स के लिए आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) लाने की योजना पर काम कर रहे हैं। लगभग 25 प्रतिशत हिस्सेदारी घटाने पर पर विचार किया जा रहा है। अगस्त या सितंबर के आसपास इसके वक्त को लेकर स्थिति साफ होने की उम्मीद है।

क्या आप उन सुधारों के बारे में विस्तार से बता सकते हैं, जिसकी योजना कंपनी बना रही है?

वर्तमान वित्त वर्ष को कोल इंडिया में सुधार के वर्ष के रूप में देखा जा रहा है। हमने अन्वेषण, निकासी संबंधी बुनियादी ढांचे, मार्केटिंग, मानव संसाधन (एचआर) और अनुसंधान और विकास (आरऐंडडी) में सुधार के 60 उपायों की पहचान की है। इनमें अन्वेषण और भूवैज्ञानिक मानचित्रण में आर्टीफिशल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के एकीकरण के साथ ही हाइड्रोलिक और इलेक्ट्रो-हाइड्रोलिक ड्रिलिंग सिस्टम की ओर बदलाव शामिल है। मार्केटिंग संबंधी सुधारों में आयातित कोयले पर निर्भरता कम करना और शक्ति नीति व्यवस्था का सुचारु रूप से लागू करना शामिल है।

मानव संसाधन सुधारों में क्या है?

एक प्रमुख पहल कर्मचारी स्वास्थ्य और मानसिक बेहतरी की नीति है। यह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के हिसाब से एक अनूठी पेशकश है। दूसरी नीति कॉरपोरेट कम्युनिकेशन है। मशीनीकरण, डिजिटलीकरण और फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी की व्यवस्था भी मानव संसाधन नियंत्रण में मदद कर रहे हैं। भर्ती अब काफी हद तक कार्यकारी पदों और भूमि अधिग्रहण से जुड़े रोजगार तक सीमित है। मध्य स्तर के प्रबंधन की भी कमी थी। हम अब तेजी से पदोन्नति करके इसका समाधान कर रहे हैं। हाल ही में हमने लगभग 550 अधिकारियों को ई-4 से ई-5 स्तर तक पदोन्नत किया है। वरिष्ठ स्तर पर और पदोन्नति की भी योजना है।

विविधीकरण परियोजनाओं के लिए धन कैसे जुटाएंगे?

सीआईएल पारंपरिक रूप से ऋण-मुक्त रही है। कंपनी ने ऐतिहासिक रूप से ऋण बाजारों का रुख नहीं किया है। हालांकि कोयला गैसीकरण जैसी विविधीकरण परियोजनाएं 70:30 ऋण-इक्विटी संरचना के हिसाब से होंगी। लखनपुर गैसीकरण परियोजना के लिए बैंकों को चिह्नित किया गया है और ऋण इसी वर्ष मिलना शुरू हो सकता है। निकासी से जुड़े बुनियादी ढांचे, रेल प्रणाली और कैप्टिव नवीकरणीय परियोजनाओं जैसी आंतरिक परियोजनाओं के लिए आंतरिक संसाधनों से धन लगाया जाना जारी रहेगा।

वित्त वर्ष 2027 के लिए उत्पादन और आपूर्ति का क्या लक्ष्य है?

इस साल बिजली और गैर-बिजली दोनों क्षेत्रों से अपेक्षित मांग का मूल्यांकन करने के बाद सीआईएल का उत्पादन लक्ष्य 81.5 करोड़ टन रखा गया है, जबकि 85 करोड़ टन आपूर्ति का लक्ष्य है। दक्षता को अब न केवल उत्पादन के संदर्भ में मापा जाएगा, बल्कि आपूर्ति और लदान के हिसाब से भी देखा जाएगा। यदि हम 81.5 करोड़ टन उत्पादन करते हैं और 85 करोड़ की आपूर्ति करते हैं, तो वित्त वर्ष 2027 के अंत तक इन्वेंट्री लगभग 3.5 करोड़ टन घटकर 9.5 करोड़ टन रह सकती है।

यदि आप स्टॉक घटाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो क्या इससे उपभोक्ताओं को गुणवत्ता संबंधी चिंता नहीं होगी?

ग्राहक हमारी रणनीति के केंद्र में हैं। सभी डिस्पैच के लिए हमारी थर्ड पार्टी सैंपलिंग व्यवस्था है। रेल और मैरी-गो-राउंड व्यवस्था से चलने वाले लगभग आधे कोयले को अब कोल हैंडलिंग प्लांट साइलो व्यवस्था से रूट किया जा रहा है, जहां ताजे और स्टॉक किए गए कोयले को स्वचालित कन्वेयर सिस्टम से मिलाया जाता है, ताकि गुणवत्ता एकसमान बनी रहे।

कोयला गैसीकरण परियोजनाओं में क्या प्रगति है?

सबसे आधुनिक गैसीकरण परियोजना महानदी कोलफील्ड्स के तहत ओडिशा में लखनपुर में है। परियोजना में लगभग 25,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा, जिसकी क्षमता 6,60,000 टन अमोनियम नाइट्रेट की है। हम ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के तहत आसनसोल के पास और वेस्टर्न कोलफील्ड्स के तहत चंद्रपुर के पास परियोजनाओं का भी मूल्यांकन कर रहे हैं, जिनके विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार किए जा रहे हैं। खासकर पश्चिम एशिया संकट ने कोयला गैसीकरण भारत के लिए रणनीतिक महत्त्व को उजागर किया है।

क्या पश्चिम एशिया संकट का असर सीआईएल पर पड़ा है?

मुख्य रूप से डीजल और एक्सप्लोसिव्स लागत बढ़ने से असर पड़ा है। हालांकि उपलब्धता कोई मसला नहीं है। सीआईएल और इसके कॉन्ट्रैक्टर प्रमुख डीजल उपभोक्ता हैं। परिचालन के के हिसाब से फिलहाल कोई व्यवधान नहीं है, क्योंकि आपूर्ति काफी हद तक हो रही है।

वित्त वर्ष 2026 में सीआईएल का लाभ 11 प्रतिशत गिर गया। वित्त वर्ष 2027 में वित्तीय प्रदर्शन बेहतर बनाने के लिए आपकी क्या योजना है?

पिछला वित्त वर्ष कुछ हद तक मिश्रित था। उत्पादन वृद्धि अपेक्षाकृत मामूली रही, लेकिन हम मांग पूरी करने और रणनीतिक भंडार संतोषजनक बनाए रखने में सक्षम थे, जो ऊर्जा सुरक्षा व आपूर्ति में स्थिरता के हिसाब से महत्त्वपूर्ण है। कम गर्मी व भारी बारिश से पिछले साल कोयले की मांग कम रही। हालांकि जनवरी से मांग बढ़ी है। इस वर्ष देश में बिजली की मांग पहले ही 256 गीगावाट के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच चुकी है।

ताप बिजली उत्पादन परियोजनाओं में सीआईएल की शुरुआत कैसी है?

हम दामोदर घाटी निगम के साथ साझेदारी में चंद्रपुर में 1,600 मेगावाट की अल्ट्रा-सुपर-क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना विकसित कर रहे हैं। इसे वित्त वर्ष 2031 से चालू किए जाने का लक्ष्य है। हम ओडिशा में महानदी बेसिन पावर प्रोजेक्ट को भी आगे बढ़ा रहे हैं।

Date 11.05.26

Publication: Business Standard

Major reforms in the works: Coal India CMD

Q&A Coal India Ltd (CIL), the world's largest coal miner, is preparing for one of its biggest strategic transitions in recent years as the state-run company focuses on reducing pithead inventories, modernising evacuation infrastructure, pursuing diversification projects, and accelerating reforms across operations. In an interview with **Saket Kumar** and **Sudheer Pal Singh** in New Delhi, CIL's Chairman and Managing Director (CMD) **B Sairam** spoke about the company's supply-focused strategy, gasification projects, funding plans, fresh listings of subsidiaries, and thermal power expansion. Edited excerpts:

What are the top three priorities currently on your list?

■ The three key priorities for CIL right now are supply or offtake, production, and large-scale reforms and consolidation. Supply has become the top priority because we began this year with around 130 million tonnes (mt) of coal stock at our pitheads. Over time, we aim to reduce inventory to more optimal levels of around 50 mt for operational flexibility. Last year, we produced 768 mt, and inventory was close to 20 per cent of annual production. Our effort is to gradually moderate this ratio closer to 10 per cent.

Does consolidation also include the listing of subsidiaries?

■ Yes, definitely. Last year, we listed BCCL and CMPDI, and both performed well, strengthening our confidence in investor appetite for mining-sector companies. Post-listing, CMPDI appreciated around 16 per cent, while BCCL appreciated around 43 per cent. Today, CMPDI's market capitalisation (mcap) is around ₹14,000 crore, while BCCL's mcap is around ₹15,500 crore. This year, we are progressing with initial public offering plans for South Eastern Coalfields and Mahanadi Coalfields.

Can you elaborate on the reforms the company is planning?

■ We have identified 60 reform measures across exploration, evacuation infrastructure, marketing, human resources (HR), and research and development. These include artificial intelligence and machine learning integration in exploration and geological mapping, along with a shift towards hydraulic and electro-hydraulic drilling systems. On the marketing side, reforms include reducing dependence on imported coal at imported coal-based power plants and smoother implementation of SHAKTI policy mechanisms.

What are the HR reforms you referred to?

■ One major initiative is an employee health and mental well ness policy, which is a unique proposition in public-sector undertaking parlance. Another is a policy on corporate communications. Mechanisation, digitalisation, and first-mile connectivity systems are also helping in manpower containment, while recruitment is now largely limited to executive positions and land-acquisition-linked employment. There was also a gap at middle-management levels. We are now addressing this through faster promotions.

How will CIL fund its diversification projects?

■ CIL has traditionally remained debt-free and has historically not approached debt markets. However, diversification projects such as coal gasification will follow a 70:30 debt-equity structure. Bankers have been identified for the Lakhanpur gasification project, and the debt drawdown process may begin this year. For internal projects such as evacuation infrastructure, rail systems, and captive renewable projects, funding will continue through internal accruals.

What are the production and supply targets for FY27?

■ This year, CIL's production target has been fixed at 815 mt after evaluating anticipated demand from both the power and non-power sectors, while the supply target is higher at 850 mt. Efficiency will now be measured not only in terms of production, but also supply and dispatches. If we produce 815 mt and

supply 850 mt, inventory could reduce by around 35 mt to 95 mt by the end of FY27.

If you focus on liquidation of stocks, would it not raise concerns among consumers about quality?

■ Customers are at the centre of our strategy. We have third-party sampling mechanisms for all dispatches. Nearly half the coal moving through rail and merry-go-round systems is now routed through Coal Handling Plant silo systems, where fresh and stocked coal are blended through automated conveyor systems to ensure consistency in quality.

What is the progress on coal gasification projects?

■ The most advanced gasification project is at Lakhanpur in Odisha under Mahanadi Coalfields. The project involves an investment of around ₹25,000 crore and a planned ammonium nitrate capacity of 660,000 tonnes. We are also evaluating projects near Asansol under Eastern Coalfields Limited and near Chandrapur under Western Coalfields, with detailed project reports under preparation.

Has the West Asia crisis affected CIL?

■ (It has) mainly through higher diesel and explosives costs, although availability has not been an issue. CIL and its contractors are major diesel consumers. However, operationally, there has been no disruption because supplies remain largely available.

CIL's profit dropped 11 per cent in FY26. What are your plans to improve financial performance in FY27?

■ The last financial year was somewhat mixed. While production growth remained relatively moderate, we were able to adequately meet demand and maintain comfortable strategic coal stocks, which was important from the perspective of energy security and supply stability. Last year was an aberration for coal demand. Moderated summer temperatures and heavy rainfall were the main reasons for subdued demand. However, demand has picked up since January. This year, India has already met a record peak power demand of 256 gigawatts (Gw). Analysts say demand could touch 270 Gw during May or June, especially because of El Niño conditions. We are fully prepared to meet whatever demand arises. We are hopeful of a better financial performance this year.

More on business-standard.com

Date 11.05.26

Publication: Business Standard

Coal India plans ₹1 trn capex push over 5 yrs

For asset monetisation, the company is aiming to list two of its subsidiaries by year-end. In a strategic shift, CIL may approach debt markets for the first time to fund diversification projects such as coal gasification under a 70:30 debt-equity structure. A significant portion of the planned spending has been earmarked for modernising evacuation systems and reducing dependence on pithead stockpiles, which have surged in recent years due to weaker-than-expected coal demand.

"We are consciously making efforts to place fresher coal into the market and move towards a more demand-aligned 'produce and sell' approach, rather than prolonged stocking before sale. This is expected to improve operational efficiency as well as consumer satisfaction," Sairam said, describing the change as a paradigm shift in CIL's operational strategy.

CIL began FY27 with more than 130 million tonnes (mt) of coal stock at pitheads. The company now plans to gradually reduce this to around 50 mt while increasing direct supply to consumers. Sairam said performance would increasingly be measured in terms of supply and dispatches rather than production alone.

A key pillar of this transition is the expansion of first-mile connectivity (FMC) infrastructure. Under this plan, CIL will invest around ₹25,000 crore over the next four years in conveyor systems, silos and mechanised rail-loading facilities to improve coal evacuation and handling efficiency.

The company currently operates 46 FMC projects with handling capacity of 432 mt. Another 13 projects with capacity of 133 mt are being added this year. By FY30, CIL aims to raise the number of FMC projects to 94, with total handling capacity rising to nearly 995 mt.

The capex push will also support CIL's diversification strategy into coal gasification, thermal power and critical minerals. The company is developing a ₹25,000 crore coal gasification project at Lakhanpur in Odisha in partnership with Bharat Heavy Electricals Ltd. CIL and Damodar Valley Corporation (DVC) are also jointly developing a 1,600 megawatt (Mw) ultra-super-critical thermal power project at Chandrapura, with an estimated investment of around ₹20,000 crore. The project is expected to be commissioned by FY31. In a major strategic shift, Sairam said CIL could approach debt markets for the first time in its history to part-fund diversification projects. "CIL has traditionally remained debt-free. Historically, we have not approached debt markets," he said, adding that bankers had already been identified for the gasification project.

Separately, the company plans to list two more subsidiaries during the current financial year, including South Eastern Coalfields Ltd and Mahanadi Coalfields Ltd, following strong investor response to the recent listings of Central Mine Planning and Design Institute Ltd and Bharat Coking Coal Ltd.